राष्ट्रीय पुस्तक व्यापार निगम

*433. **श्री कपिल वर्मा :**
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय पुस्तक व्यापार निगम का गठन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार एजेंसियों द्वारा हर वर्ष बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है और यदि हां, तो ऐसे प्रकाशनों की संख्या क्या है और उनके लिए बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है, और ;

(ग) इन पुस्तकों की बिक्री के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्थायें की गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग और उनके द्वारा स्थापित अनेक स्वायत्त संगठन अपने कार्यकलापों से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित करते हैं । इनमें से कुछ समूल्य प्रकाशन हैं जो बिक्री के लिए होते हैं, शेष प्रकाशनों का वितरण इस ढंग से किया जाता है जिसे पुस्तकें प्रकाशित करने वाली ऐजेंसी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है । जहां तक पुस्तकों की बिक्री का संबंध है इसकी पद्धति, निजी बिक्री माध्यमों और इस उद्देश्य के लिए विशेष-रूप से स्थापित बिक्री केंद्रों में भिन्न-भिन्न है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) मुख्यतया अपनी स्वायत्त एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित करता है । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पुस्तक वितरण एजेंसी स्थापित करने संबंधी एक परियोजना तैयार करने की की जिम्मेदारी सौंपी है । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने परियोजना से संबंधित एक व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए टाटा कन्सल्टैन्सी सर्विसेज को नियुक्त किया है ।

उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता

*434. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं ;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई और कितनी राशि आवंटित की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि आवंटित राशि, मांगी गई राशि की अपेक्षा कम है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांग की अपेक्षा कम राशि आवंटित किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) महोदय, उत्तर प्रदेश में तीन कृषि विश्वविद्यालय हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा मांगा गया विकास अनुदान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा रिलीज की गयी राशि संलग्न विवरण में दी गयी है। **(नीचे देखिए)**

(ग) कुछ मामलों में आवंटित राशि मांगी गयी राशि से कम थी ।

(घ) अनुदान की राशि योजना के अंतर्गत उपलब्ध कुल आबंटित धनराशि को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की गई थी ।